



3-9-83

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 310] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 1983/आषाढ 28, 1905
No. 310] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 1983/ASADHA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्र संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(वित्तिक कार्य विभाग)

वीधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1983

का०आ० 509 (अ):— कुछ वर्षों से गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश में कई गुना वृद्धि हो गई है। ऐसी कम्पनियों की संख्या काफी ज्यादा है जिनके शेयर भारी मात्रा में इन वित्तीय संस्थाओं के पास हैं। यद्यपि इन संस्थाओं ने सहायता प्राप्त करने वाली कम्पनियों में अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए आंतरिक—मार्ग निवेश निर्धारित किए हैं, तथापि अब इस दिशा में गहराई से अध्ययन करना आवश्यक हो गया है जिससे ऐसी नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सुझाव दिए जा सकें जो राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के अनुकूल हों और जिनसे इस प्रकार की सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए पूंजी निवेश के संरक्षण की सुनिश्चित अवस्था हो। इसलिए एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है जो सहायता-प्राप्त कम्पनियों में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए पूंजी निवेशों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार

करेगी और इस मामले में सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

2. समिति के लिए विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे:—

- (1) निवेश प्राप्त कम्पनियों में सार्वजनिक हित के संरक्षण के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली मौजूदा प्रणाली की जांच करना और उसमें सुधार करने के उपायों का सुझाव देना तथा ऐसी कम्पनियों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा मनोनित निदेशकों के लिए समुचित मार्ग-निर्देश तैयार करना ;
- (2) वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण मंजूर करते समय लागू किए जाने वाले "सपरिवर्तनीयता-खण्ड" के प्रवर्तन तथा उसके प्रभाव की जांच करना तथा यदि वांछनीय हो तो उसमें उचित परिवर्तनों का सुझाव देना ; और
- (3) उपर्युक्त मद संख्या (1) तथा (2) से सम्बन्धित किसी भी अन्य मामले पर सुझाव देना।

3. समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

- | | |
|--|------------|
| (1) श्री एम० नरसिम्हम् | अध्यक्ष |
| (2) डा० बिमल जलान,
मुख्य आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक कार्य विभाग | सदस्य |
| (3) डा० अर्जुन सेन गुप्त,
प्रधान मंत्री के अतिरिक्त सचिव | सदस्य |
| (4) श्री एम० आर० बी० पूंज,
अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | सदस्य |
| (5) श्री एस०एस० नाडकर्णी,
प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश
निगम | सदस्य |
| (6) श्री एच० टी० पारेख | सदस्य |
| (7) श्री ए० घोष,
डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक | सदस्य |
| (8) डा० एन० के० सेनगुप्त,
संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग | सदस्य-सचिव |

4. आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 1983 तक पेश कर देगी।

[सं० एम० 3/(32)-सी०सी०आई० (II)/83]
पी० के० कौल, सचिव

Ministry of Finance

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 1983

S.O.509 (E).—Over the years, investments by public financial institutions in the private corporate sector have grown manifold. There are a large number of companies where the financial institutions have substantial shareholding. Though these institutions have evolved internal guidelines in regard to their interests in the assisted companies, it has now become necessary to undertake an indepth study to suggest measures for evolving policies which can subserve national interests and also ensure protection of investments made by such public financial institutions. Therefore, it has been decided to set up a high level Commit to

to look into various aspects related with investments made by public financial institutions in the assisted companies, and to make recommendations to the Government in the matter.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows:

- (i) to look into the existing system adopted by the financial institutions for safeguarding the public interest in the invested companies and to suggest measure for effecting improvement therein as also devising of appropriate guidelines for Directors nominated by the financial institutions in such companies;
- (ii) to look into the working and the impact of the convertibility clause imposed by the financial institutions while sanctioning loans and to suggest changes if considered desirable; and
- (iii) to make suggestions on any other matter which is connected with or incidental to (i) and (ii) above.

3. The composition of the Committee will be as follows:—

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Shri M. Narasimham |Chairman |
| (2) Dr. Bimal Jalan,
Chief Economic Adviser,
Department of Economic Affairs | Member |
| (3) Dr. Arjun Sen Gupta
Addl. Secretary to Prime Minister | Member |
| (4) Shri M.R. B. Punja,
Chairman,
Industrial Development Bank of
India | Member |
| (5) Shri S.S. Nadkarni
Managing Director, Industrial
Credit & Investment Corporation
of India | Member |
| (6) Shri H.T. Parekh | Member |
| (7) Shri A. Ghosh,
Deputy Governor,
Reserve Bank of India | Member |
| (8) Dr. N.K. Sengupta,
Joint Secretary,
Department of Economic Affairs |Member-
Secretary |

4. The Committee is expected to submit its report by 31st October, 1983.

[No. S. 3/(32)-CCI (II)/83]
P. K. Kaul Secy.